गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल बरकरार

यूपी में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 30 नवंबर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू पेराई सीजन 2018-19 के लिए गन्ने के दामों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि चुनावी वर्ष होने से गन्ने की कीमतों में प्रतीकात्मक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ने की सामान्य किस्म का राज्य परामर्शी मूल्य (एसएपी) 315 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य में गन्ने की पेराई तेजी पकड़ रही है।

राज्य के किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि डीजल, श्रम, उर्वरक समेत कृषि इनपुट लागतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि निजी मिल मालिकों ने यह बात फिर दोहराई थी कि वे वर्तमान राज्य परामर्शी मूल्य पर ही किसानों को गन्ने का भुगतान करने की हालत में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस समय चीनी के दाम कम बने हुए हैं और बाजार का परिदृश्य भी कमजोर बना हुआ है। ऐसे में गन्ने के दाम बढ़ाने से बकाये में और बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में 94 निजी चीनी मिलें हैं।

पिछले कई वर्षों से चीनी कंपनियां यह मांग कर रही हैं कि गन्ने की कीमतों को चीनी के खुदरा दामों पर आधारित बनाया जाए ताकि किसानों और मिल मालिकों सहित सभी भागीदारों को लंबी अवधि में कोई परेशान न हो। उनका कहना है कि यह कीमत निर्धारण का तर्कसंगत तरीका है।

किसानों की थी मांग

- चुनावी वर्ष होने से कीमतों में प्रतीकात्मक बढ़ोतरी की थी उम्मीद
- किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की थी

हालांकि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि उसने पहले इस मुद्दे का अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी। पेराई सीजन 2017-18 में उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 120 लाख टन से अधिक रहा और किसानों का कुल बकाया 354 अरब रुपये तक पहुंच गया।

हालांकि वैश्विक चीनी बाजार में अति आपूर्ति और इसकी वजह से घरेलू बाजार में कीमतें गिरने के कारण पेराई सीजन के अंत में बकाया काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस समय बकाया करीब 42 अरब रुपये है।

किसान हर सीजन में मांग से कम गन्ने की कीमत मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा बढ़ता जा रहा है। पेराई सीजन 2018-19 में रकबा 26 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है। यह 2017-18 में 22 लाख हेक्टेयर से 18 फीसदी अधिक है। इसकी एक वजह यह है कि भुगतान में देरी के बावजूद गन्ना किसान राज्य परामर्शी मूल्य प्रणाली को धान, गेहूं जैसी अन्य नकदी फसलों की तुलना में बेहतर पाते हैं।

गन्ना किसान नेता अरविंद सिंह ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि धान और गेहूं का भुगतान कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं होता, इसलिए किसानों के पास एकमात्र विकल्प गन्ना ही बचता है। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि किसान गन्ने की खेती को तरजीह देते हैं। लेकिन एसएपी प्रणाली कम से कम गन्ने के भुगतान के लिए गारंटी मुहैया कराती है, भले ही देरी से।' सिंह ने इस बात पर निराशा जताई कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की।

उन्होंने कहा, 'इस साल गन्ने का रकबा बढ़ा है, लेकिन यह अगले पेराई सीजन (2019-20) में घटेगा क्योंकि हाल में कृषि इनपुट लागतों में बढ़ोतरी की पर्याप्त भरपाई नहीं हुई है।' इस बीच निजी मिलों के लिए बकाया चुकाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर आज समाप्त हो रही है, लेकिन अब भी उन पर करीब 40 अरब रुपये का बकाया है।